शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 24-1 जुलाई 2024 मूल्य पांच रूपये

कमलेश के लिये आसान नहीं होगी चुनावी डगर शान्ता कुमार ने दी परिवारवाद की संज्ञा

- देहरा की बेटी के कार्ड को बदलकर होशियार सिंह ने नादौन की बहू करार दिया
- अब देहरा के बेटे और नादौन की बहू में मुकाबला
- कमलेश के शपथ पत्र पर होशियार सिंह की शिकायत कानूनी उलझने खड़ी करेगी

शिमला/शैल। प्रदेश में तीन उपचुनाव होने जा रहे हैं। दस जुलाई को मतदान होगा। चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। इन उपचुनावों के परिणामों का सरकार और विपक्ष

पर कोई ऐसा संख्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे सरकार की स्थिरता पर कोई सवाल खड़े हो पायें। लेकिन इस सबके बावजूद यह उपचुनाव पिछले उपचुनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये हैं। क्योंकि देहरा से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। स्मरणीय है कि लोकसभा की चारों सीटें कांग्रेस हार गयी हैं। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हार मिली है। लोकसभा के साथ हुये छः विधानसभा उपचुनाव में से चार कांग्रेस जीत गयी है। लेकिन यह जीत भाजपा के आन्तरिक समीकरणों के गणित का प्रतिफल मानी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिल पाये हैं। इस परिदृश्य में मुख्यमंत्री की पत्नी का देहरा से उम्मीदवार बनाया जाना निश्चित रूप से कई सवालों को जन्म देता है। क्योंकि यदि किन्हीं कारणों से देहरा कांग्रेस हार जाती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर ऐसे सवाल उठेंगे जिन्हें हाईकमान भी नजरअन्दाज नहीं कर पायेगी।

मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। संगठन में भी वह ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं रही है जिसकी कोई अपनी अलग राजनीतिक पहचान बन पायी हो। इस नाते उनकी केवल एक ही पहचान है कि वह मुख्यमंत्री की पत्नी है। इससे अलग कमलेश ठाकुर ने अपने को देहरा की बेटी होने का भी भावनात्मक अस्त्र छोड़ा है। चुनावी मंचों से वह लगातार यह बोलना नहीं भूल रही है कि **''ध्याण को खाली हाथ नहीं भेजते''**। उसी के साथ उसने यह भी ऐलान किया है कि यदि नादौन को सुक्खू सरकार सौ रूपये देती है तो वह देहरा के लिये एक सौ एक लेकर आयेगी। देहरा में ही उनका और मुख्यमंत्री का कार्यालय होगा। वह यह सब कहकर देहरा के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि चुनावों के बाद देहरा में उनकी लगातार उपलब्धता बनी रहेगी। लोगों को अपने कार्यो के लिये मुख्यमंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह पूरी तरह इस चुनाव को भावनात्मक रंग दे रही है। होशियार सिंह के खिलाफ यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पन्द्रह माह के कार्यकाल में देहरा में विकास का एक भी काम नहीं किया है। कमलेश यह दावा कर रही है कि वह जीत कर देहरा में विकास की गंगा बहा देगी।

दूसरी और होशियार सिंह ने कमलेश के भावनात्मक कार्ड की जो काट लोगों में रखी है उससे यह

चुनाव निश्चित रूप से रोचक और गंभीर हो गया है। देहरा की बेटी के नैरेटिव को बदलते हुये होशियार सिंह ने तथ्य सामने रखा है उनका मायका

शेष पृष्ठ 8 पर.....

इन उपचुनावों ने भाजपा की नीयत और नीति पर उठाये सवाल

- भाजपा नेतृत्व आक्रामकता से पीछे हटा नजर आ रहा
- कांग्रेस से ज्यादा भाजपा नेतृत्व के लिए कसौटी होते जा रहे यह उपचुनाव

शिमला/शैल। क्या इन उपचुनाव में भाजपा सफलता हासिल कर पायेगी? यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि लोकसभा में जहां भाजपा ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर 2014 और 2019 की तरह इस बार भी कब्जा कर लिया है वहीं पर भाजपा छः विधानसभा उपचुनावों में से चार हार गई है। जबकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार यह फैला रहा था कि इन चुनावों के बाद प्रदेश की सरकार गिर जायेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह हार भाजपा के आपसी तालमेल में अभाव और सरकार के साथ रिश्तों की घनिष्ठता पर उठते सवालों के नाम लगी। अब इन तीन उपचुनावों में भाजपा को यह प्रमाणित करना है कि उसमें कोई गुटबाजी नहीं है और जनता में उसकी स्वीकार्यता बराबर बनी हुई है। इसलिए उसने 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। इस परीक्षा में यह उपचुनाव प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपने को प्रमाणित करने का अवसर होगा। अन्यथा यही कहा जायेगा कि लोकसभा की जीत तो मोदी के नाम पर हो गयी। लेकिन प्रदेश स्तर पर स्थानीय नेतृत्व अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है।

विधानसभा के लिये उपचुनावों की स्थिति क्यों पैदा हुई पूरा प्रदेश जानता है। सरकार और कांग्रेस लगातार यह कहती आ रही है कि भाजपा धनबल के सहारे सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। दूसरी और भाजपा और उपचुनाव में गए सारे कांग्रेस के बागी और निर्दलीय मुख्यमंत्री के अपेक्षा पूर्ण व्यवहार को इसका कारण बताते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ विधायकों के बिकाऊ होने तथा हर बार अपने व्यक्तिगत कामों के लिये ही उनके पास आने का आरोप लगाते आ रहे हैं। जबकि इन नौ लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीत आरोप लगाये हैं। मुख्यमंत्री की पक्षपात पूर्ण कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व इन नौ लोगों द्वारा उठाये गये आरोपों को इस आक्रामकता के साथ आगे नहीं बढ़ा पाया है। जबकि चुनाव में आक्रामकता ही सबसे बड़ा हथियार होती है।

यह सही है कि जयराम के शासनकाल भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ दायर किये अपने ही आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नहीं

शेष पृष्ठ 8 पर.....

नशे के खिलाफ ठोस व बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित 'हिमाचल के प्रहरी' सम्मान समारोह में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों का पता लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका

निभाने वाले 18 व्यक्तियों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के इन प्रहरियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में असाधारण प्रतिबद्धता और बहादुरी का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा है, जो सीमाओं और जनसांख्यिकी से परे है। यह परिवारों को बाधित करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने समुदायों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के अभिशाप से बचाने के लिए सतर्क और सक्रिय होना चाहिए। इस खतरे का मुकाबला करने के प्रयासों के लिए एक ठोस और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानून प्रवर्तन, सामुदायिक जुड़ाव, शिक्षा और पुनर्वास शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपने 16 माह के कार्यकाल में देवभूमि में नशे के खिलाफ अपने आपको सक्रिय तौर पर जोड़ा है। उन्होंने बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज गांव-गांव तक नशा पहुंच रहा है और अब लड़कियां तक ड्रग पैडलर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए हमारे शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस कानून की प्रभावशीलता न केवल अधिकारियों पर बल्कि जनता की सतर्कता और सहयोग पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि हम देवभूमि के उन प्रहरियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने नागरिक कर्तव्यों से परे जाकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने में अनुकरणीय साहस और समर्पण दिखाया है। उनके प्रयासों ने न केवल अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने में मदद की है, बल्कि नशा मुक्त समाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रहरियों की जिम्मेदारी की भावना ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित किया है।

इससे पूर्व, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश द्वारा लोगों के सामूहिक प्रयासों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जो नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सम्मान समारोह हमारे जागरूक नागरिकों की सक्रिय भूमिका को मान्यता देने और उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है, जो सहयोग की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग हिमाचल प्रदेश में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती पेश करता है और इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए शिक्षा, रोकथाम, उपचार और पुनर्वास शामिल करने वाला एक बहु-विषयक दृष्टिकोण आवश्यक है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पारंपरिक प्रवर्तन उपाय अकेले नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मूल कारणों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। समस्या को उत्पन्न करने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित कारणों को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता को पहचानते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्य गुप्तचर विभाग ने एक बहुआयामी एंटी-ड्रग रणनीति का प्रस्ताव रखा है। यह रणनीति विभिन्न हितधारकों और संसाधनों को एकीकृत करती है ताकि इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संकट से मुक्त वातावरण बनाया जा सके।

राज्यपाल ने पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समाज के सभी वर्गों से वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बनने और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग देने की अपील की है।

वह सोलन के निकट शमलेच में सभ्या रि-फोरेस्टर्स सोसाइटी द्वारा

आयोजित नौवें वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि वन हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार एक पेड़ दस पुत्रों के समान होता है।

शुक्ल ने कहा कि समाज को वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की जरूरत है जिसके लिए जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए।

उन्होंने पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिस्थितियों में तेजी से हो रहे बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में वनों की कटाई इसका एक मुख्य कारण है।

शुक्ल ने पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वयसेवकों, विशेषकर विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने सभ्या रि-फोरेस्टर्स सोसाइटी द्वारा पिछले आठ वर्षों से वृक्षारोपण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के बाद पौधों की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे सोसाइटी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। सोसाइटी द्वारा अब तक 10 हजार पौधे लगाये जा चुके हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने सोसायटी के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कभी 15 से 16 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ यह संगठन अब 500 लोगों का एक बड़ा वृक्ष बन गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर देवदार का पौधा भी रोपा। उन्होंने सोसायटी द्वारा आयोजित पोस्टर एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने सम्पूर्ण क्रान्ति आंदोलन महोत्सव का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। जेपी आंदोलन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में

सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन महोत्सव का आयोजन किया गया।

महोत्सव का शुभारम्भ करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जयप्रकाश नारायण को भारत के नव निर्माण का महान नायक बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज देश में लोकतन्त्र को नई दिशा मिली है। देश के नव निर्माण आन्दोलन में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। देश की स्वतन्त्रता संघर्ष और देश के निर्माण में उनका योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। राज्यपाल ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यथार्थवादी थे और उन्होंने सपनों को हकीकत में बदला। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि लोक नायक जय प्रकाश अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विकास केन्द्र द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं और इनके माध्यम से उनकी स्मृतियों को संजोकर रखा जा रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए 12 लोगों को जेपी सेनानी सम्मान से सम्मानित किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन के पूर्व प्रधानमन्त्री प्रो. सम्डोंग रिन्पोचे, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री बीके त्रिपाठी, शोधार्थी, विचारक और समाज सेवी उपस्थित रहे।

टोल प्लाज़ा पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं: डॉ. अभिषेक जैन

शिमला/शैल। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्य और सुविधाओं की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि सड़कें प्रदेश के विकास का आधार हैं और प्राधिकरण को राज्य में बेहतर राजमार्ग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को टोल प्लाज़ा पर शौचालय, एंबुलेंस, क्रेन टोल प्लाज़ा मेडिकल ऐड पोस्ट और ट्रैफिक ऐड पोस्ट के माध्यम से वाहन चालकों और यात्रियों की प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर इन पोस्ट का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाज़ा कर्मचारी नेम प्लेट व वर्दी में रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील है इसलिए प्राधिकरण को फोरलेन के लिए पहाड़ियों का कटान वैज्ञानिक तरीके से करना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजनाओं का निर्माण करते हुए रिटेनिंग वॉल, क्रैश बैरियर और नाईट रिफ्लेक्शन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजनाएं पर्यटकों और यात्रियों के समय और धन की बचत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है इसलिए इसका निर्माण समयबद्ध रूप से किया जाना चाहिए।

डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि टोल प्लाज़ा पर बेहतर ट्रैफिक प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वाहन चालकों और यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन टोल प्लाज़ा में कॉन्ट्रेक्टर को आपातकालीन स्थिति में क्रेन, राजमार्ग पर निगरानी और एंबुलेंस की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 259340 सामान्य तथा सेवा अहर्ता मतदाता

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन के अन्तिम दिन तक अद्यतन की गई मतदाता सूचियों के अनुसार तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों में कुल 255417 सामान्य तथा 3923 सेवा अहर्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 93831, देहरा में 84694 तथा हमीरपुर में 76892 सामान्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि देहरा में सबसे अधिक 1826, हमीरपुर में 1173 जबकि नालागढ़ में 924 सेवा अहर्ता मतदाता हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 6523 मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु के, 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 3334, शतायु 72 तथा 2390 दिव्यांगजन मतदाता हैं।

उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा उप-चुनाव के दृष्टिगत तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रपत्र 12डी के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1576 व 423 दिव्यांगजन मतदाओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है।

उन्होंने बताया कि आगामी उप-चुनावों के लिए कुल 315 मतदान केन्द्रों में से नालागढ़ में 121, देहरा में 100 तथा हमीरपुर में 94 केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

पौंग बांध विस्थापितों के लिए कानून भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों की समस्या को समझता हूं। हमारी सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती, बल्कि घर बनाने के लिए तीन गुणा राशि देती है। देहरा की जनता और पौंग बांध विस्थापितों के लिए अगर कानून भी बदलना पड़े तो बदलेंगे। चुनाव आचार संहिता के कारण अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन, विस्थापितों की हर संभव मदद की जाएगी।

मुख्यमंत्री देहरा में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान यूथ कांग्रेस के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व आजाद विधायक ने अपने राजनीतिक फायदे व लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विधायकी बेची है। वह भाजपा की राजनीतिक मंडी में दूसरी बार विधायक बनने के 14 माह बाद ही बिक गये।

ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि लोगों ने उन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए आजाद विधायक चुना था। वह जिसकी सरकार आती उससे काम करवा सकते थे। देहरा की जनता को होशियार से पूछना चाहिए कि वह न कांग्रेस के थे न भाजपा के, फिर क्या मुसीबत आ पड़ी कि इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही थी तो भाजपा के साथ विपक्ष में बैठ जाते, उपचुनाव थोपने की जरूरत क्या थी। उन्हें विधायक व ऐच्छिक निधि मिलती रहती, उससे जनता के काम करते। भाजपा व होशियार सिंह ने जनभावनाओं से खिलवाड़ करते हुए यह उपचुनाव जबरदस्ती थोपा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकने के बाद होशियार सिंह एक महीना देहरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आये। सरकार गिराने में लगे रहे, इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे। कोई आजाद विधायक ऐसे इस्तीफा नहीं देता, यह सामान से भरे उस अटैची का दबाव था जो भाजपा से मिला था। जल्दी इस्तीफा मंजूर करने का दबाव निर्दलीय विधायक

इसलिए बना रहे थे, क्योंकि दूसरी किस्त विधायकी छोड़ने के बाद ही मिलनी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होशियार सिंह बतायें, देहरा की जनता व सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कभी धरना दिया। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। जिस कमल को खिलाने के लिए भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, होशियार सिंह ने उसकी कमल को खरीद लिया। भाजपा के कर्मठ व ईमानदार कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वह कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें, चूंकि यह चुनाव कांग्रेस और बिके हुए विधायक के बीच है। होशियार सिंह ने देहरा का विकास रोक रखा। अगर पूर्व विधायक महीने का 15 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो फिर क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करवाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम देहरा में उन्होंने शुरू करवाया, फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई। 680 करोड़ की लागत से जूलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, जिसमें जंगल सफारी, बड़े होटल व अन्य सुविधाएं होंगी। 2000 युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। मेरा युवाओं से आग्रह है कि 10 जुलाई को भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति पर वोट के जरिये चोट करें। यह समय कमल खरीदने व जनता को धोखा देने वालों को सबक सिखाने का है। देहरा की जनता कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताकर भेजे, साढ़े तीन साल में क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी और अथाह विकास होगा। यह चुनाव ईमानदारी व बेईमानी के बीच है। बिकाऊ पूर्व विधायक ने देहरा की जनता से बार-बार झूठ बोला, क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कमलेश के जीतने के बाद देहरा की हर समस्या हल कर दी जाएगी। देहरा की जनता सरकार में भागीदार बनने के लिए वोट करें, विपक्ष में बैठने के लिए। सरकार के साथ चलने पर ही देहरा विकास की नई गाथा लिखेगी।

इस मौके पर आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, चेयरमैन कैबिनेट रैंक भवानी पठानिया, विधानसभा में डिप्टी व्हिप केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रत्न, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, चेयरमैन नरदेव कंवर, संजय चौहान, पूर्व विधायक योगराज, अजय महाजन, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पिंदर ठाकुर, पूर्व उम्मीदवार पवन ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुलविंदर इत्यादि मौजूद रहे।

सुख-सम्मान निधि योजना से हो रहा महिला सशक्तिकरण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्त्वकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जिला ऊना के हरोली में 7,280 महिलाओं को 3.27 करोड़ रुपये से लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश की 48,000 महिलाओं को तीन महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपये प्रति महिला वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उत्थान और कल्याण की दृष्टि से शुरू की गई इस अभिनव योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना से महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही है और सम्मानजनक तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यह योजना लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि तमाम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने और समाज के चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।

लोक निर्माण मंत्री ने द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन का निर्माण 145.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। 99 कमरों की सुविधा वाले इस निकेतन में हिमाचल के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने और इसे समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आर.एस. बाली ने पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने कहा कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली के तहत पर्यटन अधोसंरचना के सतत

विकास के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रदेश में व्यवसाय के अवसरों पर चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय और बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में अग्रसर है। सरकार पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से राज्य की आर्थिकी को मज़बूत बनाने के साथ-साथ युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए एशियन विकास बैंक के अंतर्गत तैयार की जा रही परियोजनाओं के विकास, प्रबन्धन एवं संचालन में निजी क्षेत्र की साझेदारी सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भविष्य में देश के अन्य स्थानों में भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने डिजाइन, साझेदारी संरचना और एडीबी की उप-परियोजनाओं आदि के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कीं। प्रस्तुति के दौरान निजी निवेशकों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों में विशेष रूचि दिखाई।

प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मानसी सहाय ठाकुर, ताज, आईटीसी, महिन्द्रा, ओबरॉय, सरोवर आदि जैसे प्रमुख होटल समूहों के प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्रों से डिलॉयट व पीडब्ल्यूसी परामर्श एजेंसी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, मनीला और नई दिल्ली से एशिया विकास बैंक के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना लागू करेगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 6,297 प्री-प्राइमरी अनुभाग संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 60 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में 2,377 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्यों के शिक्षा विभाग को व्यापक प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा विभाग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के सभी चार प्रारूपों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इन चार प्रारूपों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों, पूर्व में स्थापित प्री-प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे और प्री-प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 6,297 विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार अनुशिक्षक रखेगी। सरकार की यह पहल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्यार्थियों को उनके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का समावेश करना प्रदेश सरकार का मूल ध्येय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरने जा रही है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है।

उस व्यक्ति ने अमरत्त्व प्राप्त कर लिया है, जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या कर्ज बढ़ाने के लिए कांग्रेस को सत्ता दी थी?

इस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति यह हो गयी है कि सरकार को हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है। अब तक यह सरकार करीब तीस हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लेने की बाध्यता बन गयी है। कैग अपनी रिपोर्ट में इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार को चेतावनी भी जारी कर चुका है। इस सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश की स्थिति श्रीलंका जैसी होने की आशंका व्यक्त करते हुये चेतावनी जारी की थी। इस चेतावनी के परिपेक्ष में आते ही डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाया। बिजली, पानी की दरें बढ़ाई। विधानसभा चुनावों के दौरान जो गारंटीयां जनता को दी थी उन पर अमल स्थगित किया। युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था उस पर अमल नहीं किया जा सका। विधानसभा में रोजगार के संबंध में पूछे गये हर सवाल में सूचना एकत्रित की जा रही है का ही जवाब आया है। बेरोजगारी में प्रदेश देश के पहले पांच राज्यों की सूची में आ चुका है। सस्ते राशन की दरें बढ़ाने के साथ ही उसकी मात्रा में भी कमी कर दी गई है। सत्ता में आते ही सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालय में खाली पदों का पता लगाने के लिए एक मंत्री कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकारी विभागों में ही सत्तर हजार पद खाली हैं। अकेले शिक्षा विभाग में ही बाईस हजार पद खाली है। आज शिक्षा विभाग में स्कूलों में जो परीक्षा परिणाम आये हैं उनके बाद अध्यापकों पर सख्ती बढ़ाने और उनसे जवाब देही मांगने की बातें हो रही हैं। लेकिन इन खाली पदों में कितने इस दौरान भरे जा सके हैं इसकी कोई जानकारी नहीं आ पायी है। विभाग में पांच आउटसोर्स के माध्यम से नई भर्तियां किये जाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के कर्मचारी इसी प्रक्रिया के तहत भरे गये हैं इसका भविष्य प्रश्नित है। इस समय सरकार नियमित रूप से स्थाई भर्तीयां करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि सरकार की आर्थिक सेहत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

इस वस्तुस्थिति में जो सवाल खड़े होते हैं उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पहला सवाल यह खड़ा होता है कि प्रदेश की स्थिति के लिये जिम्मेदार कौन है। निश्चित रूप से प्रदेश में रही सरकारें और उनकी नीतियां ही इसके लिये जिम्मेदार रही हैं। उन नीतियों पर निष्पक्षता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रदेश में उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिये आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिये जो निवेश किया गया है और उद्योगों को आमंत्रित करने के लिये जो वित्तीय सुविधा उनको समय-समय पर दी गयी हैं उनके बदले में जो कर और गैर कर राजस्व तथा रोजगार इसमें मिला है आज इसका निष्पक्ष आकलन करने की आवश्यकता है। इन उद्योगों की सुविधा के लिये स्थापित किये संस्थाओं वित्त निगम, एसआईडीसी, खादी बोर्ड आदि आज किस हालत में हैं। प्रदेश को बिजली राज्य प्रचारित करके उद्योग आमंत्रित किये गये बिजली परियोजनाएं स्थापित की गयी। लेकिन क्या आज प्रदेश का बिजली बोर्ड और उसके साथ खड़े किये गये दूसरे संस्थान आत्मनिर्भर हो पाये हैं। उनसे कितना राजस्व प्रदेश को मिल रहा है और प्रदेश के सार्वजनिक संस्थाओं का कर्जभार कितना है कितना ब्याज उनको चुकाना पड़ रहा है। क्या इसका एक निष्पक्ष आकलन किये जाने की आज आवश्यकता नहीं है। क्या यह एक स्थापित सच नहीं है कि उद्योगों की मूल आवश्यकता उसके लिये आवश्यक कच्चा माल और उपभोक्ता दोनों में से एक का उपलब्ध होना जरूरी होता है। कितने उद्योगों के लिये प्रदेश इस मानक पर खरा उतरता है यह सब आज जवाब मांग रहा है।

यह एक बुनियादी सच है कि जब आर्थिक संसाधनों की कमी हो जाये तो घर के प्रबंधकों को अपने खर्चो पर लगाम लगानी पड़ती है। क्या इस समय के प्रबंधक ऐसा कर पा रहे हैं। क्या जनता ने उसके सिर पर कर्ज भार बढ़ाने के लिये अपना समर्थन दिया था। इस समय सरकार के प्रबंधन पर नजर डाली जाये तो क्या यह नहीं झलकता की कर्ज लेकर घी पीने के चार्वाक दर्शन पर अमल किया जा रहा है। इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि इस कर्ज का निवेश कहां पर हो रहा है। यह जानने का जनता को हक हासिल है। विपक्ष की पहली जिम्मेदारी है यह सवाल उठाना लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब चुनाव के मौके पर भी पक्ष और विपक्ष इस बुनियादी सवाल से दूर भाग जायें तो क्या यह सवाल अदालत के माध्यम से नहीं पूछा जाना चाहिए। क्योंकि वित्तीय स्थिति पर एक चेतावनी जनता को पिला दी गयी। एक श्वेत पत्र की रस्मअदायगी हो गयी पक्ष और विपक्ष चार दिन इस पर शोर मचाने की औपचारिकता के बाद चुप हो गये। तो क्या अब इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जाना चाहिए? क्योंकि यदि यही स्थिति चलती रही तो प्रदेश का भविष्य क्या हो जायेगा? क्या जनता ने कर्ज की कीमत पर गारंटीयां मांगी थी? शायद नहीं। प्रदेश में आयी आपदा पर किस तरह से राहत का आकार बढ़ाकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपायी थी और उसका सच अब पहली बारिश में सामने आ गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक करोड़ लोगों को जागरूक करेगा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली स्थित डॉ.अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री रामदास अठावले, ब्रह्माकुमारीज के दिल्ली क्षेत्रीय समन्वयक राजयोगिनी बीके लक्ष्मी तथा सामाजिक न्याय और

अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 700 लोग व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे तथा लगभग 500 गैर-सरकारी संगठनों के एक लाख से अधिक लोग वर्चुअल रूप से जुड़े थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि नशे की लत को खत्म करने की चुनौती से निपटने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर इस सामाजिक उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी गैर-सरकारी संगठनों और आध्यात्मिक संगठनों की सराहना की। इसके लिए युवाओं में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक करोड़ लोगों को जागरूक करेगा और समाज के सामूहिक प्रयासों से 100 दिनों के भीतर देश भर के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नशे की लत न केवल नशा करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। उन्होंने सभी गैर-सरकारी संगठनों से नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनके नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने में उनकी मदद करेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने अपने भाषण में मंत्रालय की एनएपीडीडीआर योजना पर प्रकाश डाला एवं उसकी सराहना की और बताया कि किस प्रकार नशा मुक्त भारत अभियान ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने में मदद की है। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव ने अपने स्वागत भाषण में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला।

सुखमंच थियेटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे की लत के दुष्प्रभावों तथा पूरे समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया।

मादक पदार्थ उपयोग विकार एक ऐसा मुद्दा है, जो देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। किसी भी मादक पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी बाधित करती है। विभिन्न मनो-सक्रिय पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की उस पर निर्भरता बढ़ जाती है। कुछ मादक पदार्थ यौगिक न्यूरो-मनोवैज्ञानिक विकारों, हृदय संबंधी बीमारियों के साथ-साथ दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसलिए, पदार्थ के उपयोग और उस पर निर्भरता को एक मनो-सामाजिक -चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, समस्या की सीमा का आकलन, निवारक कारवाई, उपयोगकर्ताओं के उपचार और पुनर्वास, सूचना के प्रसार के सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया है और वर्तमान में यह देश के सभी जिलों में संचालित है। इसका उद्देश्य युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और समुदाय तक पहुंच बनाई जा रही है। इस अभियान में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाया जा रहा है।

नशा मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियां:

जमीनी स्तर अब तक पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूक किया गया है, जिनमें 3.50 करोड़ से अधिक युवा और 2.32 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

3.35 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचा है।

8,000 से अधिक कुशल स्वयंसेवकों (मास्टर वालंटियर्स-एमवी) की एक मजबूत टीम की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी।

एनएमबीए गतिविधियों के आंकड़ों को एकत्रित करने और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba-dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

नशा मुक्त होने के लिए आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1.67 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।

युवाओं व अन्य हितधारकों को जोड़ने और उनसे जुड़ने के लिए 'नशे से आजादी-एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संपर्क कार्यक्रम', 'नया भारत, नशा मुक्त भारत', 'एनसीसी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान संपर्क' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान को सहयोग देने तथा जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, राम चंद्र मिशन (दाजी), इस्कॉन तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके इस अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।

जिलों और कुशल स्वयंसेवकों द्वारा वास्तविक समय पर जमीनी स्तर पर होने वाली गतिविधियों का डेटा एकत्र करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रखा गया है।

सभी नशामुक्ति सुविधाओं को जियो-टैग किया गया है, ताकि आम जनता आसानी से इसका फायदा उठा सके।

हर साल 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्ध्करी निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस मनाने के लिए 20.06.2024 से 26.06.2024 तक सप्ताह भर चलने वाली ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन किया। इन गतिविधियों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, नशा मुक्त जीवनशैली के लिए योग, ध्यान और सचेत रहने को बढ़ावा देना, एनएमबीए के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन, नशा मुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल करना, नशा मुक्त भारत बनाने में निचले स्तर से महिलाओं की भूमिका आदि शामिल हैं।

देश भर के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और डीसी/डीएम से अनुरोध किया गया कि वे राज्य और जिला स्तर पर एनएमबीए के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफ र्म सहित मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार के साथ-साथ रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, शपथ जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया

शिमला। भारत में तम्बाकू के उपयोग से बहुत से रोग पैदा होते हैं और इसके इस्तेमाल से व्यक्ति मृत्यु की कगार तक पहुंच सकता है। देश में हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें तम्बाकू के कारण होती हैं। भारत तम्बाकू

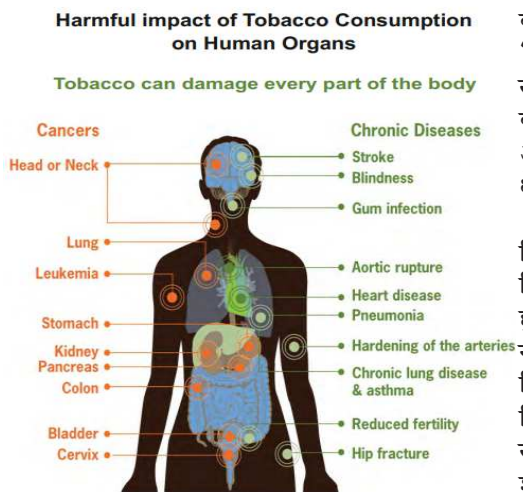

का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस) 2019 के अनुसार, देश भर में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तम्बाकू का सेवन करते पाये गये हैं।

हमारे स्कूल भवनों और परिसरों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की विभिन्न रूपों में आसान पहुँच को उपरोक्त स्थिति पैदा करने वाले प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीटीपी) के अंग के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तम्बाकू के सेवन से बचाने के लिए शिक्षा संस्थानों को तम्बाकू रहित बनाने के लिए 'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान' दिशानिर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए 'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल' विकसित किया है और इसे 31 मई, 2024 को मनाए जाने वाले विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश भर के शिक्षा संस्थानों को 'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान' दिशानिर्देशों का अनुपालन कराना और तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाना है।

तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थानों के मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों और आस-पास के क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करने की सलाह दी है। इस संबंध में 'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल' के अनुसार तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थानों के दिशानिर्देशों का उचित तरीके से अनुपालन करने के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की गई है।

शिक्षा संस्थान के परिसर में अधिकृत व्यक्ति के आदेश के उल्लेख के साथ 'तम्बाकू मुक्त क्षेत्र' का साइनेज प्रदर्शित करें।

शिक्षा संस्थान के प्रवेश द्वार /चहार-दीवारी पर अधिकृत व्यक्ति के आदेश के उल्लेख के साथ 'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थानों का साइनेज प्रदर्शित करें।

परिसर के अंदर सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े या फेंके गए गुटखा/तम्बाकू पाउच, थूकने के स्थान जैसे तम्बाकू के उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए।

शिक्षा संस्थान के परिसर में तम्बाकू के नुकसान पर पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करना।

शिक्षा संस्थानों में हर छह महीने में कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि का आयोजन करना।

'तम्बाकू मॉनिटर' का नामांकन और उनके नाम, पदनाम और संपर्क नंबर साइनेज पर दर्शाये जाने चाहिए।

शिक्षा संस्थानों की आचार संहिता में 'तम्बाकू उपयोग न करने' संबंधी दिशा-निर्देशों को शामिल करना।

शिक्षा संस्थान की चहार-दीवारी/बाड़ की बाहरी सीमा से 100 गज के क्षेत्र को चिह्नित करना।

शिक्षा संस्थान के 100 गज के भीतर की दुकानों में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे।

'तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थानों के कार्यान्वयन मैनुअल के अनुसार तम्बाकू के उपयोग के खिलाफ शपथ ली जाये।

इसके अलावा, उन्होंने नुक्कड़ नाटकों, वीडियो फिल्मों, गैर सरकारी संगठनों, संसाधन व्यक्तियों आदि द्वारा वार्ता के माध्यम से नशामुक्ति पर जागरूकता संदेश फैलाने में नागरिक समाज की भूमिका पर भी जोर दिया। तदनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा और विद्यांजलि-स्कूल स्वयंसेवी पहल के माध्यम से संसाधन व्यक्तियों, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल करें, ताकि छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए तम्बाकू की रोकथाम और उपभोग के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

जून, 2024 के प्रथम 15 दिनों में 69,166 जन शिकायतों का निवारण किया गया

शिमला। कार्मिक, लोक शिकायत और पैन्शन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 1 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में पारिवारिक पैन्शनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे। पैन्शन और पैन्शनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1-31 जुलाई, 2024 के दौरान पारिवारिक पैन्शनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 46 मंत्रालय/विभाग भाग ले रहे हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य लंबित पारिवारिक पैन्शन शिकायतों में पर्याप्त कमी लाना है। इस कार्यक्रम में पेंशन और पैन्शनभोगी कल्याण विभागों के सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण, डीजी बीएसएफ, लेखा महानियंत्रक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ 46 मंत्रालयों/विभागों के नोडल लोक शिकायत अधिकारी, सभी पैन्शन वितरण बैंकों के प्रतिनिधि और पैन्शनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

वर्तमान में, केंद्रीकृत पैन्शन शिकायत और निवारण प्रणाली (सीपीई एनजीआरएएमएस) पर प्रति वर्ष लगभग 90,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पोर्टल (URL: www.pgportal.gov.in /PENSION/) पर आवेदक द्वारा सीधे या डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा ई-मेल, डाक या टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 के माध्यम से विवरण प्राप्त होने पर, शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। कुल शिकायतों में से, पारिवारिक पैन्शन शिकायत के मामले लगभग 20-25 प्रतिशत हैं। पारिवारिक पैन्शनभोगियों की ज्यादा शिकायतें महिला पैन्शनभोगियों द्वारा की गई हैं । विशेष अभियान में निपटाये जाने वाले पारिवारिक पैन्शन संबंधी शिकायतों को सीपीई एनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से चुना गया है। अभियान के दौरान निवारण के लिए 46मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित कुल 1891 (15.06.2024 तक) पारिवारिक पैन्शन संबंधी शिकायतों की पहचान की गई है। अधिकांश शिकायतें रक्षा पैन्शनभोगियों, रेलवे पैन्शनभोगियों और गृह मंत्रालय के तहत सीएपीएफ पैन्शनभोगियों से संबंधित हैं। बैंक से संबंधित मामले भी बड़ी संख्या में हैं। डीओपीपीडब्ल्यू, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन की निगरानी कर और उन्हें मिशन मोड पर शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय/विभाग ट्वीट और पीआईबी वक्तव्यों के माध्यम से सफल कहानियों को बताएंगे। डीओपीपीडब्ल्यू ने अभियान की सफलता के लिए एक हैशटैग यानी #स्पेशलकैंपेनफैमिलीपेंशन बनाया है।

भारत सरकार की कर्मचारी पैन्शन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन

शिमला। भारत सरकार ने कर्मचारी पैन्शन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पैन्शन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पैन्शन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाये। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पैन्शन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। उपयुक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे।

प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पैन्शन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया।

अब तक, निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी, जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया है।

इसलिये, अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते थे। परिणामस्वरूप, 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही योजना छोड़ रहे थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। इसके संशोधन बाद, ऐसे सभी कर्मचारी पैन्शन योजना के सदस्य जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे।

इससे पहले, पूर्ववर्ती तालिका डी के अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के साथ, निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए, 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000/- प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850/- रुपये की निकासी लाभ का हकदार था। अब उसे 36,000/- रुपये का निकासी लाभ प्राप्त होगा।

विक्रमादित्य सिंह ने नितिन गडकरी से सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की

शिमला/शैल। लोक निर्माण निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर आगामी बरसात के दृष्टिगत प्रदेश

की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया।

केन्द्रीय मंत्री ने लोक निर्माण मंत्री के आग्रह पर जिला शिमला में केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत खमाड़ी-टिक्कर सड़क के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। लोक निर्माण मंत्री ने यह धनराशि स्वीकृत करने के लिए गडकरी का आभार व्यक्त किया।

विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय मंत्री द्वारा पूर्व में घोषित 150 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून को ध्यान में रखते हुए यह धन राशि महत्त्वपूर्ण है।

उन्होंने मंडी जिले में कमांद-कटौला और चैलचौक-पंडोह सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पहले से प्रस्तुत 30 करोड़ रुपये के अनुमानों को भी शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया क्योंकि यह वैकल्पिक सड़क मार्ग ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में काफी सहायक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यह सड़कें महत्त्वपूर्ण हैं और लोगों और पर्यटकों की सुविधा एवं कुल्लू-मनाली ट्रैफिक समस्या के समाधान में इन सड़कों का रख-रखाव महत्त्वपूर्ण है।

लोक निर्माण मंत्री ने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय मंत्री के साथ शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को टू-लेन की बजाय फोर-लेन के रूप में निर्मित करने का मामला पहले ही उठाया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को एक समान उन्नयन के लिए एनएचएआई की संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं वार्षिक मसौदा योजना (ड्राफ्ट एन्नुअल प्लान) से हटा दी गई हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को वार्षिक योजना 2024-2025 में शामिल करने का अनुरोध किया।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 के एक हिस्से के सुधार के लिए केन्द्रीय मंत्रालय की प्रस्तुत 70 करोड़ रुपये की अनुमाति राशि भी लंबित है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आगामी अगस्त माह में मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रमुख अभियंता एनपी सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश कपूर बैठक में उपस्थित थे।

350 बस चालकों की रूकी भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू:उप–मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 156वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने बेड़े में पुरानी बसों के स्थान पर 250 नई डीजल बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने का निर्णय लिया है जिस पर लगभग 105 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, निगम इस वर्ष अपने बेड़े में 24 नई सुपर लग्जरी बसें एवं 50 टेम्पो ट्रैवलर शामिल करेगा। ये 50 टेम्पो ट्रैवलर प्रदेश के दूर–दराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में पुरानी बसों के स्थान पर चलाए जाएंगे। इन बसों की खरीद निगम द्वारा अपने संसाधनों से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निगम अपने संसाधनों से लगभग 25 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद भी करेगा।

उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम द्वारा टाइप–1 327 बसें और टाइप–3 विद्युत चलित बसों की खरीद के लिए 15 जून 2024 को निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बसों में यात्रियों द्वारा कैशलेस माध्यम से किराये का भुगतान करने के लिए परिचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर मंडलीय स्तर पर तीन परिचालकों को पारितोषिक देने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी।

उन्होंने कहा कि 350 बस चालकों की रूकी हुई भर्ती प्रक्रिया को जल्द

शुरू किया जाएगा। निगम में चालकों के 600 पद रिक्त हैं और आने वाले दो वर्षों में लगभग 800 चालक सेवानिवृत हो रहे हैं इसलिए चालकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मियों को 18 जनवरी 2024 के बाद देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन भोगियों तथा पेंशन भोगियों को 55.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

श्री अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन समिति का गठन किया गया है। यह समिति निगम को हो रहे घाटे के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन के सीमित साधन हैं और लोग परिवहन सुविधा के लिए एचआरटीसी पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा महिलाओं तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को रियायती दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त निगम की बसें परिवहन सेवा से वंचित क्षेत्रो में भी सेवाएं दी रही हैं। उन्होंने बताया कि निगम सेवा भाव से कार्य करते हुए रोजाना लगभग 5 लाख यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने निगम की बसों की बेहतरीन तस्वीरें और वीडियो बना कर भेजे थे उन्हें सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार जो कर्मचारी अपने रूट पर अच्छी आमदनी करेंगे उन्हें भी निगम द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा सभी कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच करवाई जाएगी ताकि उनका बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

बद्दी व फतेहपुर में बस अड्डा निर्माण को मिलेगी प्राथमिकता

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आज बस अड्डा निगम की बैठक का भी आयोजन किया गया जिसमें नए सदस्य शामिल रहे। प्रदेश में बस अड्डों की स्थिति का जायजा लिया और उनमें सुधार करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में बन रहे बस अडडे के लंबित कार्य के दृष्टिगत प्रबंध निदेशक को कार्य कर रही एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी उन्हें अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए जाएं। इसी तरह मैक्लोडगंज और शिमला के बस अड्डों से संबंधित मामलों पर भी बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बद्दी और फतेहपुर में बस अड्डा प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि निगम की लंबित राशि को जल्द जारी किया जाए ताकि निगम के कर्मचारियों के हित में और बेहतर निर्णय लिए जा सकें।

बैठक का संचालन प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम रोहन चंद ठाकुर ने किया और उप–मुख्यमंत्री तथा गैर–सरकारी सदस्यों को निगम द्वारा आगे भी बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया।

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की 51वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम की स्थापना हुई है और मौजूदा वक्त के बदलते परिदृश्य के अनुसार इस निगम का प्रशासनिक एवं संरचनात्मक पुनर्गठन किया जाएगा। इस कदम से अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

बैठक में निगम से संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा नई भर्तियों सहित अन्य मांगों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1296.45 लाख रुपये का ऋण तथा दिव्यांगजनों को इसी अवधि में 540.83 लाख रुपये का ऋण निगम द्वारा रियायती ब्याज दर पर दिया गया है।

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने तथा अपने व्यवसाय के लिए कम दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदकों को छोटे व्यवसायों, परिवहन सेवाओं, दुकानों, पार्लर एवं कृषि आदि क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक जिनकी वार्षिक आय 98 हजार रुपये या इससे कम है तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक जिनकी वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रुपये या इससे कम है, उन्हें अधिकतम 30 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार जिनकी सालाना पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम है, ऐसे पुरूषों को 8 प्रतिशत एवं महिलाओं को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम 30 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। शिक्षा के लिए भी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण आवंटित किया जाता है।

इसी प्रकार दिव्यांगजनों को 50 हजार तक का ऋण 5 प्रतिशत, 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत, 5 लाख से 15 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत, 15 लाख से 30 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत तथा 30 लाख से 50 लाख रुपये तक का ऋण 9 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है।

निगम द्वारा स्थापना से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के 3486 लाभार्थियों तथा 1900 दिव्यांगों को 159.68 करोड़ रुपये का ऋण 31 मार्च, 2024 तक दिया गया है।

बैठक में सचिव सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार, निदेशक ईसोम्सा किरण भड़ाना, निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रदीप कुमार और निगम के निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आईजीएमसी की एचआईवी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रदेश की पहली प्रयोगशाला बनी

शिमला/शैल। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि आईजीएमसी, शिमला के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचआईवी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली प्रयोगशाला बन गई है।

उन्होंने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी के अंतर्गत कार्यरत माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचआईवी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला को 27 मई, 2024 को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के साथ आईएसओ 15189:2012 एनएबीएल: 112 की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

उन्होंने बताया कि यह प्रयोगशाला उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण उच्च मानकों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है और एनएबीएल द्वारा यह प्रमाणीकरण बताता है कि यह प्रयोगशाला गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

एम सुधा देवी ने कहा कि प्रशिक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भारतीय गुणवत्ता परिषद् का एक घटक बोर्ड है, जिसमें प्रशिक्षण की तकनीकी दक्षता के लिए प्रयोगशाला का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन शामिल है। एचआईवी निदान प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह गुणवत्ता क्षमता के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। यह मान्यता निदान परिणामों की विश्वसनीयता और सटीकता को बल देती है जो प्रभावी रोगी प्रबन्धन और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह रोगियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नियामक निकायों के बीच प्रयोगशाला की क्षमताओं की विश्वसनीयता भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, एनएबीएल मान्यता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है तथा निरंतर सुधार और सुदृढ़ गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली को बढ़ावा देती है। यह उच्च गुणवत्ता वाली पद्धतियों को बनाये रखने में प्रयोगशाला का समर्थन करता है और एचआईवी महामारी को नियन्त्रित करने और प्रतिबन्धित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रदेश ने एनईएसडीए में अनिवार्य 56 ई–सेवाओं की परिपूर्णता का लक्ष्य हासिल किया

शिमला/शैल। डिजिटल तकनीक विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के डिजिटल तकनीक विभाग ने विभिन्न विभागों के समन्वय से एनईएसडीए में अनिवार्य 56 ई–सेवाओं की सौ फीसदी परिपूर्णता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन फ्रेमवर्क के मानकों के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य ने इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है और सिर्फ छ: महीनों में 40.89 फीसदी सुधार हुआ है। जलशक्ति व शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड ने बीते कुछ महीनों में सराहनीय प्रदर्शन किया है। इस प्रगति से राज्य की रैंकिंग भी बढ़ेगी। एनईएसडीए के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों से आग्रह किया गया है कि शेष मानकों पर निरंतर कार्य करें।

उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक विभाग ने यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस के सहयोग से सभी विभागों के प्रतिनिधियों को हिम डाटा पोर्टल और एनईएसडीए फ्रेमवर्क पर प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस ने इस दौरान राज्य सरकार की एनईएसडीए फ्रेमवर्क में प्रभावी आकलन और प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट साझा की।

इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस में भारती इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की निदेशक पॉलिसी डॉ.आरुषि जैन ने राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोर्टल (himdataportal.com) ई–गवर्नेंस सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए ओपन डाटा पारिस्थितिकी का संवर्धन करेगा। हिम डाटा पोर्टल प्रदेश सरकार के डाटा के लिए वन–स्टॉप मंच है। इस संबंध में एनईएसडीए ने हाल ही में दिशा–निर्देश दिए थे।

पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि राज्य के नागरिकों, उद्योगपतियों और पॉलिसी निर्माताओं की उच्च गुणवत्ता डाटा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस द्वारा विकसित किया गया यह पोर्टल अब राज्य सरकार को सौंपा जा रहा है।

भारत सरकार के सभी स्तरों पर एनईएसडीए फ्रेमवर्क ई–गवर्नेंस सेवाओं के प्रतिपादन तंत्र का व्यापक आकलन है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था।

एनईएसडीए का उद्देश्य मौजूदा ई–गवर्नेंस सेवाओं के प्रतिपादन तंत्र के प्रभाव का आकलन करना है। राज्य की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस को डिजिटल प्रगति के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।

नामांकन वापसी के उपरान्त 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप–चुनावों में नामांकन वापसी के उपरान्त अब कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि देहरा में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापिस नहीं लिया तथा यहां कुल पांच, हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार के नामांकन वापसी के बाद अब तीन व नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी गुरनाम सिंह की नामांकन वापसी के बाद अब पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश (53) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, होशियार सिंह (57), भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी सुलेखा देवी (59), अरूण अंकेश स्याल (34) तथा एडवोकेट संजय शर्मा (56) चुनावी मैदान में हैं।

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा (37) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डॉ. पुष्पिंदर वर्मा (48) इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी नन्द लाल शर्मा (64) चुनावी मैदान में हैं।

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बावा (44) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, के.एल. ठाकुर (64) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), किशोरी लाल शर्मा (46) स्वाभिमान पार्टी तथा निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत सिंह (36) व विजय सिंह (36) चुनावी मैदान में हैं।

मोदी के नेतृत्व में देश में शक्तिशाली हो रहा:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मन की बात कार्यक्रम के प्रमुख संजीव कटवाल ने बताया की पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 6549 बूथों पर हुआ जिसमे 787588 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

उन्होंने बताया की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने देहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मन की बात कार्यक्रम सुना।

कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, डॉ. सिकंदर कुमार, अभी पदाधिकारियों, विधायकों और जिला मंडल यूनिट द्वारा सुना गया। यह कार्यक्रम सीधा-सीधा प्रधानमंत्री और देश को जोड़ने वाला कार्यक्रम है कुछ समय से यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की वजह से स्थगित था और अब फिर प्रारंभ हुआ है।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा की पीएम मोदी ने विदेशों में भारत की धाक के उदाहरण गिनाए जो की हमारे लिए गर्व की बात है। तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म-जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सूरीनाम तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ने अपनी भारतीय विरासत को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। सूरीनाम में हिन्दुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को भारतीय आगमन दिवस और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है। यहां तो हिंदी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है। जयराम ठाकुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शक्तिशाली हो रहा है और हमारी संस्कृति का प्रचार है अब देश की सीमाओं को लांघता हुआ प्रचंड रूप से बाहर निकल गया है।

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा की जैसे-जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोकल फ र वोकल को दृष्टि से भारत के कितने ही उत्पाद हैं, जिनकी दुनिया-भर में बहुत मांग है और जब हम भारत के किसी स्थानीय उत्पाद को वैश्विक होते देखते हैं, तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है।

एक पेड़ मां के नाम , पीएम मोदी ने सबसे पूछा कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे- मां। बिंदल ने कहा की हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां, हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है। हर मां, अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन, और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है- एक पेड़ मां के नाम। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को जोरो शोरो से चलाएगी।

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा की पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक पर भी बात, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों

का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे हम भाजपा की ओर से भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं । हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं । टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। उसके बाद से ही हमारे एथलीट पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी-जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें, तो इन सबने करीब 900 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी।

जयराम, अनुराग, बिंदल को उपचुनाव की दृष्टि से मिले अपने अपने केंद्र

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा की गई एक नोटिफिकेशन में बताया गया की हिमाचल प्रदेश में हो रहे तीन विधानसभा क्षेत्रों नालागढ़, हमीरपुर एवं देहरा के उप-चुनावों में प्रभारी, सह-प्रभारी, संयोजक एवं सह-संयोजक पूर्व में निर्धारित किए गए हैं जो अपने कार्यो का सफल संचालन कर रहे हैं। चुनाव के संचालन को और अधिक गंभीरता देने हेतु निम्न नेताओं में विशिष्ट कार्य विभाजन किया गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया की नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हमीरपुर विधानसभा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर और देहरा विधानसभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष रूप में देखेंगे। बिंदल ने बताया की उपरोक्त सभी वरिष्ठ नेतागण सम्पूर्ण चुनावों की देखरेख के साथ-साथ विशेषरूप से उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों की चिंता करेंगे।

हिमाचल आन सेल के लिए बाजार सजा रही सरकार:सुधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक सुधीर शर्मा ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ने की बजाय कांग्रेस की सरकार हिमाचल आन सेल के लिए बाजार सजाने लग पड़ी है। पहले यह बाजार दुबई में सजाया

गया और पालमपुर की बेशकीमती जमीन को निजी हाथों में देने की योजना बनाई गई। लेकिन जब विरोध हुआ तो यह मामला थोड़ा थम गया। अब फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग के चेयरमैन और अधिकारियों की फौज से साथ चंडीगढ़ से एक बड़े होटल में यह बाजार सजाया है। उन्होंने बताया कि एशियन डिवेल्पमेंट बैंक से लोन लेकर सरकार प्रदेश में बड़े-बड़े होट्लस बनाने जा रही है। जिसे सरकार अपने चहेतों को न्यूनतम दामों पर लंबी अवधि से लिए पहले ही सौंपने की तैयारी कर रही है। जबकि एडीबी द्वारा अभी तक राज्य सरकार के साथ लोन एग्रीमेंट साईन तक नहीं किया गया है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि मित्रों की यह सरकार सब कुछ औने-पौने दामों पर चहेतों को सौंपने की तैयारी कर रही है। क्या हिमाचली बेरोजगार युवक सरकार की ऐसी दरियादिली वाली योजनाओं के काबिल नहीं हैं। सरकार क्यों नहीं छोटी-छोटी पर्यटन इकाईयां बनाकर राज्य के बेरोजगारों को लंबी अवधि की लीज पर दे देती। उन्होंने कहा कि हिमाचल का पर्यटन विकास निगम लगभग 140 करोड़ के घाटे पर चल रहा है और सरकार निगम के नए होटल बनाने जा रही है। जिस पर राज्य सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर एडीबी से लोन लेकर बड़े होटल बनाकर सरकार निजी क्षेत्र के अपने चहेते लोगों को देने की तैयारी कर रही है। इसमें बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एडीबी सहित कुल 6 विभागों के कार्यालय जिस भवन में चल रहे हैं। सरकार वहां पर एक कल्ब बनाना चाहती है। जबकि वहां पर चल रहे सभी कार्यालयों को मित्रमंडली के निजी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। सरकारी खजाने से हर माह मित्रमंडली को 20 लाख रूपये से ज्यादा किराया देने की कोशिश भी हो रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल को बेचने की जो कोशिश सुक्खू सरकार द्वारा की जा रही है भाजपा उसका न केवल विरोध करेगी बल्कि राज्य के बेरोजगारों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

कांग्रेस मंत्री की टिप्पणी राज्यपाल के पद एवं गरिमा का अपमान:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा की हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के निर्णय एवं कार्यशैली के ऊपर वर्तमान कांग्रेस और उनके मित्र मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी वह अवांछनीय है।

उन्होंने कहा कांग्रेस के विभिन्न बयान हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए माननीय राज्यपाल के प्रति पूरी तरह से अपमान है।

यह बात निश्चित रूप से कही गई थी की फाइलें मंत्री महोदय के पास है और उसके बाद मंत्री द्वारा बार-बार मीडिया के अंदर इस बात को उछालना की मान्य राज्यपाल ने किसी विशेष कार्य को रोक कर रखा है, यह टिप्पणी राज्यपाल के पद एवं गरिमा का अपमान करना है।

बिंदल ने कहा कि यह सरकार लगातार लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के हनन के लिए जानी जाती है। लोकतंत्र हनन वाली है यह सुखविंदर सिंह सुक्खू कि कांग्रेस सरकार। बिंदल ने मांग की कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदार मंत्री जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, उन्हें महामहिम राज्यपाल से सार्वजनिक क्षमायाचना करनी चाहिए।

कांग्रेस के अपने विधायकों से ही कांग्रेस को खतरा:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस हारी है और 68 में से 61 सीटों पर हारी है। कांग्रेस सरकार की पूरी ताकत केवल कुर्सी बचाने के लिए लगी है इसके अलावा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और दो दिन बाद उनकी पत्नी को टिकट मिल जाती है, मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं मुझे पता है की मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना यह चयन संभव नहीं है और खासकर कांग्रेस पार्टी में।

वर्तमान सरकार में प्रदेश के हालात कैसे बन गए हैं, 17 महीने में 300 से ज्यादा बलात्कार और 150 से अधिक हत्या के मामले सामने आये हैं, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी सुनी सुनाई घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होने लग गई है, जुडशियल कॉम्पलेक्स में किराए के गुंडे एक व्यक्ति पर गोलियां चलती है जो घायल हो जाता है। उनको लाने वाले और कोई नहीं बल्कि बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक के बेटे हैं जो कि अभी तक पकड़े नहीं गये हैं। इनको सरकार का पूर्ण संरक्षण मिला है और इसका प्रमाण इससे दिखता है कि उस पूर विधायक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनके बेटे को छुपाने की छूट मिल रखी है। बिलासपुर में बच्चा-बच्चा बोल रहा है कि चिट्टे का धंधा इनके संरक्षण में चल रहा है, इस चिट्टे के दौर में इसको रोकने के लिए प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दी जा रही है, वह इसलिए क्योंकि इसी सरकार के लोग इस धंधे को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी है फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, भाजपा ने तय किया है कि कानून व्यवस्था के गंभीर मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

जयराम ने पत्रकारों के सवाल की उत्तर में कहा 9 भाजपा विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई भी अधिकार नहीं है, जब केवल इन सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नियमों और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष केवल मुख्यमंत्री की कठपुतली बनके रह गया है, न जाने मुख्यमंत्री ने उनको किस पदों का प्रलोभन दिया है।

विधानसभा अध्यक्ष को अपनी भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह कहते हैं कि 6 विधायकों के सर कलम कर दिए हैं और 3 आरे के नीचे है, जो फड़फड़ा रहे हैं। यह भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष की योग्यता की प्रदर्शन पर दाग है, अध्यक्ष निष्पक्ष होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बचाने वाली नहीं है, यह हमारी वजह से नहीं परंतु कांग्रेस के अपने विधायकों से ही कांग्रेस को खतरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीएस मामले के नतीजे से कांग्रेस नेताओ को डर लग रहा है।

सुक्खू सरकार का खिताब तालाबंदी की सरकार:डॉ.जनक

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक डॉ. जनक राज ने कहा की कांग्रेस की मित्रों की सरकार के राज में स्कूल के बच्चों की वर्दी बंद, लोगों के घरों का पानी बंद, डॉक्टर का एनपीए बंद, नौकरी देने वाला संस्थान बंद। जनक राज ने इस सरकार को तालाबंदी की सरकार सुक्खू सरकार का खिताब दिया। उन्होंने कहा की जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से केवल मात्र प्रदेश को पीछे की ओर ले जाने का कार्य किया है, पूर्व भाजपा सरकार ने जहां स्कूल के बच्चों को वर्दी देने का बड़ा काम किया था। वहीं कांग्रेस सरकार ने इन स्कूल के बच्चों की वर्दी ही बंद कर दी, स्कूल के बच्चे जो प्रदेश और देश का भविष्य हैं उनको भी सरकार ने नहीं छोड़ा, जो सुविधा इनको मिल रही थी वह भी वापस ली गई।

उन्होंने कहा की 7 नवंबर 2023 को सीएम के आश्वासन के बाद भी अभी तक डाक्टरों के लिए एनपीए बहाल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री केवल मात्र बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है, सीएम केवल आश्वासन देते हैं पर जनता इंतजार करती रहती है और काम होता नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तब मुख्यमंत्री केवल जनता और कर्मचारियों से वादे करते हैं, पर पूरा कोई भी वादे को नहीं करते हैं। यह केवल वोट बताने की राजनीति की तरफ इशारा करता है।

देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, पर यह सपने कब टूट जाएंगे पता नहीं। नालागढ़ और हमीरपुर में भी यही हालत है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आने वाले दिनों में केंद्र की अन्य एजैन्सीयों के दखल की संभावना

- विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच के आरोप
- कुछ प्रभावशाली लोगों के पास आज भी सीलिंग से अधिक जमीन
- अढ़ाई लाख में जमीन खरीद कर सरकार को छः करोड़ से अधिक में कैसे बिकी
- जिलाधीश ने कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया।

शिमला/शैल। क्या हिमाचल में केंद्रीय जांच एजैन्सीयों का दखल बढ़ने जा रहा है? क्या इस दखल का प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा? यह सवाल अभी हमीरपुर और नादौन क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर कुछ प्रभावशाली लोगों के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की 38 घंटे की छापेमारी के बाद चर्चा में आ खड़े हुये हैं। हमीरपुर में विधानसभा के लिये उपचुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा है। इस चुनाव प्रचार में यह छापेमारी एक बड़े मुद्दे के रूप में उछल रही है। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में कांगड़ा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के किसी 16 करोड़ के ऋण को 50 लाख के लेनदेन से बट्टे खाते में डालने की चर्चा थी। इस वीडियो का प्रदेश सरकार और उसकी एजैन्सीयों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। इस वीडियो को लेकर संबंधित व्यक्ति द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाने की बात जरूर उठी थी। लेकिन पुलिस की साइट पर ऐसी कोई एफआईआर अपलोड हुई नहीं मिली थी। न ही इस एफआईआर की कोई जांच होना सामने आयी थी। इसी तरह के लोकसभा चुनाव के दौरान ही धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अब विधायक सुधीर शर्मा ने एचआरटीसी को नादौन में अढ़ाई लाख में खरीदी गयी जमीन 6 करोड़ 72 लाख में दिये जाने का मुद्दा उछाला था। सुधीर शर्मा ने अढ़ाई लाख में इस कथित जमीन की मूल सेल पर ही सवाल खड़े किये थे। सुधीर शर्मा ने डमटाल में किसी कारोबारी का 250 करोड़ का जीएसटी माफ किये जाने के मामले पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी। किसी ने भी यह नहीं कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि सरकार की कार्यशैली पर यह गंभीर सवाल थे। बल्कि इसी चुनाव के दौरान कुटलैहड़ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उप चुनाव लड़ रहे देवेंद्र भूट्टों और उसके बेटे के खिलाफ प्रशासन की शिकायत पर दो एफआईआर दर्ज होने के मामले सामने आये। इस परिदृश्य में यह सन्देश अनचाहे ही चला गया कि सरकार या उसके निकटतम के खिलाफ चाहे कितने भी गंभीर मामले क्यों न हो उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी। यहां यह स्मरणीय है कि जब राज्यसभा चुनाव में छः कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी थी तो कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया था। कांग्रेसियों की ही तर्ज पर तीनों निर्दलीयों ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया। जबकि यह लोग हर मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन देते आ रहे थे। इस क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के छः लोग सदन और पार्टी से दलबदल कानून के तहत बाहर हो गये निर्दलीयों ने भी अपने पदों से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन निर्दलीयों के त्यागपत्र स्वीकार करने में कितना समय लगा दिया गया और क्या-क्या कानूनी दावपेच सामने आये यह प्रदेश ने देखा है। कैसे बालूगंज थाना में आशीष शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई यह पूरे प्रदेश में देखा है। उस दौरान जो राजनीतिक आचरण सामने आया उससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब लड़ाई व्यक्तिगत रंजिश के स्तर पर पहुंचा दी गई है। चर्चा है कि चुनावों के बाद इन सारे विद्रोहियों ने प्रदेश की पूरी स्थिति सारे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास रखी है और शाह ने उन्हें उचित कारवाई का भरोसा दिया है। स्मरणीय है कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करके उसमें बेटियों के लिये अलग यूनिट सुरक्षित रखने का प्रावधान किया है। यह संशोधित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये अभी लंबित पड़ा है। लेकिन सरकार के संशोधन से यह सवाल खड़ा हो गया है कि 1974 में बने लैण्ड सीलिंग एक्ट के बाद आज 2023-24 में भी प्रदेश में ऐसे कितने मामले कहां-कहां पर हैं। जहां पर लैण्ड सीलिंग एक्ट पर अमल न होकर लैण्ड सीलिंग सीमा से अधिक जमीन किसी के पास है। राजस्व विभाग के पास इस आश्य का कोई अध्ययन नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शायद राजा नादौन की जागीर पर लैण्ड सीलिंग के प्रावधान इतने भर ही लागू हुये हैं कि लैण्ड सीलिंग मानकों के तहत कितने के हकदार राजा नादौन बनते थे वह उनको दे दी गई और शेष बची एक लाख कनाल से अधिक जमीन विलेज कामन लैण्ड घोषित हो गयी थी। कानून के मुताबिक विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2011 में राज्यों के मुख्य सचिवोंको स्थाई निर्देश पारित किये हैं कि ऐसी जमीनों को प्रोटेक्ट किया जाये और इसकी सूचना समय-समय पर शीर्ष अदालत को दी जाये। नादौन में शायद न तो लैण्ड सीलिंग के मानको और न ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालना हो पायी है। शायद अब यह मामला केंद्रीय एजैन्सीयों के संज्ञान में आ चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र की दूसरी एजैन्सीयां भी प्रदेश में दखल देंगी।

इन उपचुनावों में भाजपा

.....पृष्ठ 1 का शेष

की है। बल्कि जब भाजपा के जिला स्तरीय दफ्तरों के लिए जमीन खरीदी का मुद्दा आया था तब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर की खरीद पर कुछ गंभीर सवाल किये थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के इन सवालों का जवाब तब हमीरपुर में जिले के भाजपा विधायकों और अन्य पदाधिकारी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सुक्खू की अपनी जमीन खरीद पर सवाल उठाये थे। इन सवालों और प्रति सवालों के बाद दोनों ओर से युद्ध विराम हो गया था। आज भी भाजपा और सुक्खू सरकार में शायद वही विराम चल रहा है। बल्कि जो सवाल उपचुनावों के पात्र बने नौ लोग उठा रहे हैं उन मुद्दों को भी भाजपा नेता गंभीरता से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस समय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस तर्ज में सरकार के गिरने की बातें कर रहे हैं उसके अनुरूप उनके व्यावहारिक कदम नहीं हो रहे हैं। इस समय भाजपा पर यह आरोप है कि वह धन बल के सहारे सरकार गिराना चाहती है। कांग्रेस से बाहर गये लोग मुख्यमंत्री को ही इस सारी स्थिति के लिये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन लोगों ने जो सवाल मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से पूछे हैं उनका कोई जवाब नहीं आया है। यह सवाल असहज कर देने वाले हैं लेकिन इनके साथ भाजपा नेतृत्व अपनी संबद्धता और समर्थन नहीं दिखा पा रहा है और इसी से उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठ रहे हैं। इससे सरकार गिरने-गिराने के दावे राजनीतिक औपचारिकता से अधिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि इस समय आयकर की छापेमारी के बाद प्रदेश का राजनीतिक वातावरण कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। ऐसे में यह उपचुनाव कांग्रेस और मुख्यमंत्री से ज्यादा भाजपा के लिये राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा बनते जा रहे हैं। क्योंकि देहरा में मुख्यमंत्री की पत्नी के चुनावी शपथ पत्र पर भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की शिकायत ने एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी है। जिसके परिणाम इन चुनावों के परिणाम आने के बाद स्पष्ट होंगे।

कमलेश के लिये आसान

.....पृष्ठ 1 का शेष

नलसूहा में है जो की जसवां परागपुर क्षेत्र में आता है। उनका ससुराल नादौन में है इस नाते वह देहरा की बेटी नहीं बल्कि नादौन की बहु है। होशियार सिंह स्वयं देहरा से हैं। पिछले दोनों चुनाव उन्होंने देहरा का बेटा होने के नाम से जीते हैं। इसी तर्क पर वह यह सवाल रख रहे हैं कि लोग घर के बेटे को चुनते हैं या नादौन की बहू को। इसी के साथ वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह पन्द्रह माह में देहरा में कोई काम नहीं करवा पाये हैं क्योंकि सुक्खू सरकार ने देहरा को एक पैसा तक आवंटित नहीं किया। जब सरकार पूरी तरह पक्षपात करके चल रही थी तो ऐसी व्यवस्था में विधायक बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। वह सवाल कर रहे हैं कि नादौन में अपने कुछ मित्रों के दायरे से बाहर न निकल पाने के कारण ही तो लोकसभा में उनकी हार हुई है। नादौन में काम किये होते तो हार क्यों होती। इस तरह भावनात्मक पलड़े पर होशियार सिंह कमलेश पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी तरह प्रदेश भाजपा के वरिष्ठतम नेता पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने कमलेश ठाकुर को इस तरह उम्मीदवार बनाया जाना परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण करार दिया है। परिवारवाद के इस आरोप का दिल्ली से लेकर शिमला तक कोई कांग्रेस नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। फिर कमलेश के चुनावी ब्यान इस आरोप को सिद्ध कर रहे हैं।

इस चुनाव में एक गंभीर पक्ष यह सामने आया है कि कमलेश ठाकुर के चुनाव शपथ पत्र को लेकर होशियार सिंह ने एक शिकायत एसडीएम देहरा के पास दायर कर रखी है। इसमें शायद भू-संपत्तियां को लेकर कुछ गंभीर आरोप है जो आगे चलकर बड़ा कानूनी मुद्दा बन सकते हैं। वैसे कमलेश ठाकुर के शपथ पत्र के मुताबिक वह अपने पति मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू से ज्यादा अमीर हैं। यह चर्चा चल पड़ी है कि मुख्यमंत्री की पत्नी होने के क्या लाभ होते हैं। आपदा में मुख्यमंत्री ने 51 लाख दान देकर जो मिसाल कायम की थी उसे इन शपथ पत्रों के आईने में देखा जाने लगा है। क्योंकि कमलेश के शपथ पत्र के साथ मुख्यमंत्री का शपथ पत्र भी चर्चा में आ गया है। इस तरह जो चुनावी परिदृश्य अब बनता जा रहा है उससे कमलेश की एकतरफा जीत अब प्रश्नित होती जा रही है। क्योंकि कमलेश के अधिकांश चुनाव प्रचारक शिमला से हैं जिनका देहरा में अपना वोट भी नहीं है। ऐसा शायद इसलिये है कि मुख्यमंत्री स्वयं नादौन- हमीरपुर से ज्यादा शिमला के हैं।